(b) if so, the percentage of shares proposed to be disinvested;

(c) whether any discussions/meetings have been held with the management and trade unions on this issue; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir. It is proposed to undertake a phased disinvestment in Indian Airlines over three years, bringing the Government's equity holding down to 49%.

(c) and (d) Views of all concerned would be considered while taking a final decision in the matter.

Development of unused airports

4454. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have identified the unused airports in the country;

(b) if so, the State-wise details thereof;

(c) if so, the fund earmarked therefor; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) and (b) Airports authority of India have identified following airports as unused airports:—

Cuddappah, Donakonda and Warrangal in Andhra Pradesh; Passighat in Arunachal Pradesh; Rupsi and Shella in Assam; chakulia, Gaya, Jogbani, Muzzaffarpur and Raxaul in Bihar; Deesa in Gujarat; Mysore and Hassan in Karnataka; Bilaspur, Khandwa, Panna and Satna in Madhya Pradesh; Akola in Maharashtra; Jharsuguda in Orissa; Vellore in Tamil Nadu; Khowai; Kailashahar and Kamalpur in Tripura; Jhansi and Lalitpur in Uttar Pradesh and Balurghat and Malda in West Bengal.

(c) to (e) AAI is considering developing Hassan airport and a provision of Rs. 3 crores exists in the Annual Plan for 1998-99 for this purpose. As regards other unused, and idle airports, AAI has made a proposal to hand over these airports to the respective State Governments for upkeep maintenance and use. Kolhapur and Sholapur airports have already been transferred to the Government of Maharashtra on 1-2-1997 on mutually agreed terms.

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के वेतनमानों का संशोधन

4455. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के वेतनमानों और पदनामों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त संशोधन किस तारीख से प्रभावी हुए हैं;

(ग) उनके वेतन-पैकेजों में श्रेणी-वार किए गए संशोधनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारियों की लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहली अप्रैल, 1996 से अपने कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन मानों तथा पदनामों को अंगीकार कर लिया है। वेतन मानों तथा पदनामों संबंधी ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

(घ) आज तक की स्थिति के अनुसार एक समान वेतन मानों से संबंधित कोई भी मांग लंबित नहीं है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यकारियों तथा गैर-कार्यकारियों के सामान्य पदनाम तथा एकीकृत वेतनमान

स्तर	पदनाम	वेतनमान
ई-6	कार्यकारी निदेशक	रु० 11500—13500
ई-5	महाप्रबंधक	रु० 9500—11500
ई-4	उप महाप्रबंधक	रु० 7500—9900
ई-3	वरिष्ठ प्रबंधक	रु० 6500—9425
ई-2	प्रबंधक	रु० 5000—8400
ई-1	सहायक प्रबंधक	रु० 4600—7925
गैर-कार्यकारी		
एनई-7	वरिष्ठ अधीक्षक तथा समकक्ष	रु० 3450—6100
(वे 250/- रु० विशेष वेतन के रूप में पाते रहेंगे)		
एनई-6	अधीक्षक तथा समकक्ष	रु० 3300—5820
(जो कर्मचारीगण रु० 3100—5280 के वेतनमान में थे उनका रैंक, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग के क्रमशः रु० 3300—5820 तथा रु० 3300—5540 के वेतनमान में पहले से ही रहने वाले कर्मचारीगण से कम होगा)।		
एनई-5	पर्यवेक्षक तथा समकक्ष	रु० 3030—5270
एनई-4	वरिष्ठ सहायक/तकनीशियन तथा समकक्ष	रु० 2950—5070
एनई-3	सहायक तकनीशियन तथा समकक्ष	रु० 2720—4400
एनई-2	वरिष्ठ एटेन्डेन्ट तथा समकक्ष	रु० 2550—3660
एनई-1	एटीन्डेन्ट तथा समकक्ष	रु० 2400—3330

Single holding company for IA/AI

4456. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that single holding company has been proposed for Indian Airlines and Air India;

(b) if so, reasons and details thereof;

(c) whether it is being opposed by any section of employees belonging to these two bodies; and

(d) if so, whether the Government has decided to take care of such a situation?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) and (b) No such decision has been taken by the Government so far.

(c) and (d) Do not arise.